railway line have been adversely affected; and

(b- if so, by when the work on the proposed railway line would be started in full swing?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): (a) and (b) Work on conversion of Nadiad-Kapadvanj portion is already in full swing. The work on the new line portion of the project is being regulated since the new line, being in continuation of the line under conversion, cannot be put to use till the conversion has been completed.

बारुका सिंचाई परियोजना म० प्र० को स्वीकृति

7. **श्री अजीत सिंह जोगी :**

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के गरियाबन्द क्षेत्र में बारुका सिंचाई परियोजना स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है, और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० सी० शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्र में बरुका सिंचाई परियोजना की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, महानदी जलाशय परियोजना के सोपान–3 के रूप में महानदी जलाशय परियोजना प्रणाली को मानसून के दौरान अधिशेष जल व्यपवर्तित करने के लिए बरुका गांव के पास पैरी नदी पर एक उच्च बांध के निर्माण की परिकल्पना है । महानदी जलाशय परियोजना की स्थिति पर एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

महानदी जलाशय परियोजना पर स्थिति रिपोर्ट

प्रारम्भ में महानदी जलाशय परियोजना सोपान-एक प्रारम्भ में 15.36 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वर्ष 1971 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी थी। इस समय तीन सोपानों सहित एक संशोधित पर्ि योजना रिपोर्ट, जिसकी अनुमानित लागत वर्ष 1989 के मूल्यों पर 916.3 करोड़ रुपए आंकी गयी है, से छत्तीसगढ़ क्षेत्र के रायपुर तथा दुर्ग जिलों में 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की योजना है। संशोधित परियोजना रिपोर्ट केन्द्र में 2/90 के दौरान प्राप्त हुई थी। अब तक नहरों द्वारों तथा तटबन्धों के संबंध में अभिकल्प पहलू निर्बाधित किए गए हैं। सिंचाई, आयोजना, जल विज्ञान तथा वित्तीय पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां राज्य को उनकी अनुपालना हेतु 11/90 को भेज दी गयी हैं।

परियोजना :–महानदी जलाशय परियोजना में मुख्य महानदी पर एक बांध शामिल हैं, जो बाद में पोषक/लिंग नहरों की श्रृंखला के माध्यम से तंदौला, मुरुमसिलि, दुन्धा, सन्दुर तथा रुद्री नामक जलाशयों को अन्त: सम्बद्ध करेगी। इन जलाशयों के अतिरिक्त जो पैरी सहायक नदी पर अन्य बांधाओं पैरी उच्च बांध के रूप में अन्य बांध जाना जाता हैं, को मानसून के दौरान महानदी जलाशय परियोजना प्रणाली में अधिशेष जल को व्यपवर्तित करने के लिए नियोजित किया गया है ।

कार्य की स्थिति (दिसम्बर, 1990 के अनुसार) सन्दुर बांध सभी पहलुओं से पूरा हो गया है । रुद्री बराज पूरा होने की उन्नत अवस्था में है । पैरी उच्च बांध के संबंध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण/अन्वेषण पूरे किए जा चुके हैं । मुरुमसिलि बांध पर सुधार कार्य पूरे होने वाले हैं । दुधवा बांध पर सुधार कार्य पूरा होने की उन्नत अवस्था में है । पोषक/लिंक नहरों के संबंध, सन्दुर पोषक के संबंध में

95 प्रतिशत, महानदी पोषक 100 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है, महानदी मुख्य नहर–116 किलोमीटर लम्बाई पर पुनरूपेण कार्य पूरा हो गया है, मन्धार शाखा नहर-16 किलोमीटर में पुनरूपेण कार्य पूरा हो गया है। आभनगुर शाखा नहर-पूर्ण हो गयी है। परियोजना में सृजित सिचाई क्षमता छत्तीसगढ़ क्षेत्र के रायपुर/दुर्ग जिले में लगभग 2.5 हेक्टेयर है

विदेश सहायता : परियोजना को जुलाई 1981 से जून 1986 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान विश्व बैंक की सहायता मिलती रही। अनुरोध करने पर विश्व बैंक ने क्रेडिट समाप्ति की तारीख को 6/90 तक बढ़ा दिया। समाप्ति तारीख को और आगे 6/91 तक बढ़ा दिया गया है।

मध्य प्रदेश में केलो नदी पर सिंचाई बांध

8. **श्री अजीत जोगी :**
श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में केलो नदी पर सिंचाई बांध बनाए जाने की परियोजना स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री वी० सी० शुक्ल) : (क) केलो सिंचाई परियोजना जिसमें 34209 हेक्टेयर क्षेत्र को वार्षिक सिंचाई प्रदान करने तथा रायगढ़ और बिलासपुर जिलों में घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति प्रदान करने के वास्ते रायगढ़ जिले में केलो नदी पर बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है, मूल्यांकन हेतु केन्द्र में प्राप्त हुई है।

(ख) परियोजना से प्रत्याशित कोयला खदान क्षेत्र के जलमग्न होने की संभावना है। राज्य सरकार को प्रत्याशित कोयला खदान की जलमग्नता के लिए कोयला विभाग से स्वीकृति प्राप्त करनी है। परियोजना में 825 हेक्टेयर वन भूमि की जलमग्नता तथा लगभग 5000 लोगों का पुनर्वास भी शामिल है। राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करनी है। केन्द्रीय जल आयोग को परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के संबंध में पता नहीं लगा है क्योंकि राज्य सरकार को सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग, फसल उत्पादन तथा सतही जलनिकास के प्रावधानों के संबंध में सूचना देनी है। राज्य को उड़ीसा सरकार से उनके 2850 हेक्टेयर क्षेत्र की जलमग्नता के लिए भी सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

छत्तीसगढ एक्सप्रेस का परिचालन

9. **श्री अजीत जोगी :**
श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन से आगे नहीं जाती है जबकि उसके आगे भी छत्तीसगढ़ अंचल में रायगढ़ और सरगुजा जैसे विशाल जिले हैं, जो लगभग पूर्णतः आदिवासी बहुल जिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को बिलासपुर से आगे झाड़सुगड़ा तक बढ़ाया जाएगा, जिससे रायगढ़ और सरगुजा जिले के लगभग 60 हजार वर्ग कि० मी० क्षेत्र में निवास करने वाले लाखों आदिवासियों को रेल सुविधा तथा देश की राजधानी दिल्ली से सीधे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सके ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। बहरहाल, एक दैनिक गाड़ी 8477/8478-पुरी–हजरत निजामुद्दीन-कलिंग-उत्कल एक्सप्रेस रायगढ़